Fourteenth Loksabha

Session : 10
Date : 07-05-2007

Participants : Pandey Dr. Laxminarayan

>

Title: Need to take steps for need based supply of chemical fertilizers in the Country

डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर) : महोदय, कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहित करते हुए कृाकों के हित में कृषि उत्पादन वृद्धि हेतु माननीय वित्त मंत्री जी ने वर्ा 2007-08 का बजट पेश करते हुए उल्लेखित किया था कि उर्वरक सब्सिडी को 17000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 22000 करोड़ रुपया कर दिया गया है। किंतु भारतीय उर्वरक संघ द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार उनका कहना है कि अभी तक पिछली सब्सिडी 10500 करोड़ रुपये वर्ा 2006-07 बकाया है तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार ने वर्ा 2007-08 में 34000 करोड़ रुपये का प्रावधान मांगा है। विगत कई वर्ाों से उर्वरक पर सब्सिडी एक ऐसा विाय बन गया है जो कि हमेशा उर्वरकों के स्वदेशी उत्पादन में बाधक होकर आयात का मार्ग प्रशस्त करता है। वर्तमान में यदि 34000 करोड़ रुपये की सब्सिडी का प्रावधान किया जाता है तब भी प्रचलित अंतर्राट्रीय बाजार में डीएपी या संबंधित कच्चे माल को देखा जाए तो कम से कम भारतीय कृषि में उर्वरकों के प्रदाय को समुचित बनाये रखने के लिए 48000 करोड़ रुपये की सब्सिडी की आवश्यकता होगी।

इसलिए आवश्यक है कि समय रहते आवश्यक कदम उठायें। 80 प्रतिशत लघु एवं सीमांत किसान द्वारा 40 प्रतिशत रकवे में जो खेती हो रही है, वे कृषि साधन विहीन हैं। असिंचित क्षेत्र में तो यह बहुत दयनीय स्थिति में है। देश के अन्न सुरक्षा एवं स्वावलंबन को बनाये रखने के लिए प्राथमिकता के आधार पर उर्वरक उत्पादन एवं उपलब्धता पर महत्व देना आवश्यक है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों मे खाद्यान्न व अन्न उत्पादन में लोग समर्थ हों। साथ ही नागरिक आपूर्ति द्वारा उपभोक्ता को खाद्यान्न उचित दर पर मिल सकें। उर्वरकों की कमी के कारण खाद्यान्न, दाल व खाद्य तेल जिंसों के उत्पादन में गिरावट संभव है। पिछले 2 वर्ाों से मध्य प्र ादेश व राजस्थान में उर्वरक उपलब्धता में जो भारी कठिनाई हो रही है, वह बजट में सीमित प्रावधानित अनुदान की राशि से हल होना संभव नहीं है।

अत: मेरा उर्वरक मंत्री महोदय से अनुरोध है कि रासायनिक उर्वरकों की उपलब्धता मांग के अनुसार सुनिश्चित हो। इस बारे में आवश्यक कदम उठाने का कट करें।